(c) if so, the quantity of gas likely to be produced annually; and

(d) by when the country would become self-reliant in this field?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SH. T.R. BAALU): (a) The total production of gas at present is around 62 MMSCMD.

(b) No. Sir.

(c) Around 1.5 billion cubic metres per year is likely to be produced from Tapti.

(d) the production of gas from indigenous sources is projected to fall short of the domestic demand.

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड क. हुआ घाटा

*577. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निरंतर घाटे में चल रहा है, यदि हां, तो इसे अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसे वर्ष-वार कितना घाटा हुआ है, और

(ग) बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अपने वार्षिक लेखा-जोखा के अनुसार इसे किसी प्रकार का घाटा नहीं हो रहा है। अपने लेखे में दर्शायी गई ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता को शामिल करने के पश्चात् एमएसईबी ने अपनी स्थापना से 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार 804.18 करोड़ रु० का संचयी अधिशेष विद्युत उत्पादन किया है।

(ख) अपने लेखे में दर्शायी गई ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता को शामिल करने के पश्चात् 1993-94 से 1995-96 तक विगत के 3 वर्षों के दौरान वर्षवार अधिशेष का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	अधिशेष (आर्थिक सहायता समेत) (करोड़ रु० में)
1993-94	118.24
1994-95	132.40
1995-96	133.79

वर्ष 1996-97 की वार्षिक लेखे 30.9.97 के बाद ही प्राप्त होंगे।

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात् दिसंबर, 1996 में विद्युत के लिए जारी की गई न्यूनतम साझा कार्यवाही योजना का उद्देश्य राज्य विद्युत यूटिलिटीज के कार्य निष्पादन में समग्र रूप से सुधार करना है। कार्यवाही योजना में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बिजली नियामक आयोग स्थापित करने, रिटेल टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, राज्य बिजली बोर्डों की स्वायत्ता प्रदान करने और इन बोर्डों की प्रबंध संबंधी प्रक्रिया में सुधार करने, व्यावहारिक पैरामीटरों में सुधार करने को प्रोत्साहन देना ताकि आगामी 5 वर्षों में राज्य क्षेत्र का समग्र पीएलएफ न्यूनतम 65% तक का स्तर प्राप्त किया जा सके, उप-केन्द्रों और प्रमुख फीडरों को अनिवार्यतः मीटरों के जरिए विद्युत सप्लाई करना, वृहत् उपभोक्ताओं से संबंधित वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करने और बेहतर भार प्रबंध हेतु वृहत विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टाईम ऑफ डे मीटरिंग की व्यवस्था करना आदि शामिल है।

Loans granted to Industries by IFCI, ICICI, and UTI

*578. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the loans granted to various industries during the last three years by IFCI, ICICI and UTI;

(b) how many of the above have been declared as Non-performing assets and the details thereof;

(c) the action being taken for revival and better performance of these financial institutions; and

(d) the action proposed to be taken against the erring officials of the above